पूरा बेंच

अपीलीय सिविल

एस. एस. संधवालिया, प्रेम चंद जैन और एस. सी. मित्तल, जे.जे के समक्ष

परमेश्वरी,-अपीलार्थी।

बनाम

एमएसटी. संतोखी,-उत्तरदाता।

नियमित दूसरी अपील सं. 1965 का 418

31 जनवरी, 1977।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का XXX)-धारा 14 (1)-हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवर्तन से पहले एक सीमित मालिक द्वारा एक महिला को उपहार-उपहार में दी गई संपत्ति के कब्जे में ऐसी महिला-अधिनियम के प्रवर्तन के बाद क्या पूर्ण मालिक बन जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 का अर्थ पहले से विद्यमान विधि की पृष्ठभूमि के विरुद्ध और उन तथ्यों के मैट्रिक्स के आलोक में लगाया जाना चाहिए जिनके कारण इसे अधिनियमित करना आवश्यक था। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन मौजूदा हिंदू कानून की पेचीदगियों को दूर करना और उसमें आमूलचूल सुधार करना था। हिंदू कानून में संपत्ति की कई अवधारणाओं के अलावा, पहले के कानून में एक हिंदू महिला की संपत्ति दो व्यापक श्रेणियों में आती थी, अर्थात्, अपनी ज्ञात सीमाओं के साथ एक हिंदू महिला की संपत्ति, और जिसे सख्ती से स्त्रीधन कहा जाता था, अपने स्वयं के विशेष नियमों द्वारा शासित। धारा 14 के तहत विधानमंडल का बड़ा इरादा हिंदू महिला संपदा के रूप में आयोजित संपत्ति का विस्तार करना और एक महिला की स्त्रीधन संपत्ति पर लगाए गए जटिल बंधनों को हटाना और निरस्त करना था। उद्देश्य इन दोनों मामलों में संपत्ति के एक स्वतंत्र और पूर्ण मालिक के रूप में उसकी स्थिति को पहचानना है। धारा 14 का उद्देश्य केवल एक महिला लिमिटेड के मालिक के विदेशी को लाभ पहुंचाना नहीं था और ऐसे विदेशी या अंतरिती इस धारा के दायरे में नहीं हैं, जिसका उद्देश्य केवल उन महिला हिंदुओं के लिए लाभ को सीमित करना है जो तत्कालीन मौजूदा हिंदू कानून के अनुसार सीमित मालिक थीं। कानून के इतिहास और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए; धारा 14 (1) की भाषा और विशेष रूप से उसके स्पष्टीकरण को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवर्तन से पहले एक सीमित मालिक द्वारा दिए गए उपहार के तहत संपत्ति का कब्जा रखने वाली महिला इसके प्रवर्तन के बाद पूर्ण मालिक नहीं बनती है।

(पैरा 5, 26, 27 और 47)

श्रीमती चिंटी आदि बनाम श्रीमती दौल्तु आदि, ए.आई.आर. 1968 दिल्ली 264 (एफ.बी.)

असहमत।

श्रीमती चावली और अन्य बनाम हंस और अन्य 1960 पी.एल.आर. 87.

खारिज कर दिया गया।

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन द्वारा 1 मई, 1973 को मामले में शामिल कानून के निम्नलिखित प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंड पीठ को भेजा गया मामला। माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एस. संधवालिया और माननीय न्यायमूर्ति श्री मान मोहन सिंह गुजराल की खंडपीठ ने 12 अगस्त, 1974 को मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया। माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एस. संधवालिया की पूर्ण पीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. सी. मित्तल ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देने के बाद 31 जनवरी, 1977 को मामला वापस कर दियाः -

"क्या एक महिला जिसके पास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवर्तन से पहले एक सीमित मालिक द्वारा दिए गए उपहार के तहत भूमि है, वह अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पूर्ण स्वामी बन जाती है?"

श्री राज कुमार शर्मा, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, संगरूर की 2 जनवरी, 1965 की डिक्री से संवर्धित अपीलीय शक्तियों के साथ नियमित दूसरी अपील, जिसमें 13 फरवरी, 1964 को जींद के उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, श्री गुरप्रताप सिंह चहल के खर्च की पुष्टि की गई थी, जिसमें वादी के मुख्य नोट में वर्णित 7 बीघा 7 विश्वास पुख्त की भूमि के कब्जे के लिए वादी के मुकदमे का आदेश दिया गया था और पक्षकारों को अपने स्वयं के खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया गया था।

आर. एस. मित्तल, अधिवक्ता, अपीलार्थियों की ओर से।

उत्तरदाताओं की ओर से अशोक भान, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इस प्रकार दिया गयाः -

एस. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति

(1) एक संदर्भ पर इस पूर्ण पीठ के समक्ष कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में तैयार किया गया हैः -

"क्या एक महिला जिसके पास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पहले एक सीमित मालिक द्वारा दिए गए उपहार के तहत भूमि है, वह अधिनियम लागू होने के बाद पूर्ण मालिक बन जाती है?"

जिन मुख्य तथ्यों से यह मुद्दा उत्पन्न होता है, वे शायद ही विवाद में हैं। सूट की जमीन का मूल पुरुष मालिक एक मातू था। उनकी मृत्यु पर उनकी पत्नी श्रीमती. सुंदर को एक सीमित मालिक के रूप में अपनी संपत्ति विरासत में मिली। हालांकि, उन्होंने अपने पति के भाई की बेटी श्रीमती परमेश्वरी के पक्ष में खेवट संख्या 58 में एक आधा हिस्सा उपहार में दिया और इसके संबंध में उत्परिवर्तन को 28 अगस्त, 1953 को मंजूरी दी गई। जाहिरा तौर पर डोने को उक्त संपत्ति के कब्जे में रखा गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 17 जून, 1956 को लागू हुआ और उसके लगभग 5 साल बाद श्रीमती. दाता सुंदर की 1961 में कुछ समय के लिए मृत्यु हो गई। इसके बाद 2 मार्च, 1963 को श्रीमती द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया। संतोखी, श्रीमती की असली बहन। परमेश्वरी ने इस घोषणा के लिए कि बाद वाले के पक्ष में दिया गया उपहार इस प्राथमिक आधार पर अमान्य था कि श्रीमती. मूल दाता सुंदर के पास विवादग्रस्त भूमि में केवल एक जीवन संपदा थी और इसलिए, वह इसका पूर्ण उपहार देने का हकदार नहीं था। इस मुकदमे का विरोध श्रीमती ने किया था। परमेश्वरी प्रतिवादी लेकिन निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया था।

(2) अपील पर, उपर्युक्त निर्णय और डिक्री की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई थी। दूसरी अपील मेरे विद्वान भाई जैन, न्यायमूर्ति के समक्ष आई, जिन्होंने इस मुद्दे पर अधिकार के टकराव को देखते हुए प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। डिवीजन बेंच, जिसके समक्ष मामला रखा गया था, ने निर्देश दिया कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अंततः एक पूर्ण पीठ द्वारा सुलझा लिया जाना चाहिए।

(3) इन दोनों निर्दिष्ट आदेशों से यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर अधिकार का एक महत्वपूर्ण टकराव है। हालांकि, अनिवार्य रूप से पूर्ववर्ती की पेचीदगियों पर ध्यान देने से पहले क़ानून के प्रावधानों के आलोक में मामले की जांच करना नया होगा।

(4) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14, जिसके इर्द-गिर्द विवाद घूमता है, निम्नलिखित शब्दों में हैः -

“14 (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में अर्जित की गई किसी भी हिंदू महिला के स्वामित्व वाली संपत्ति को उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के रूप में धारण किया जाएगा, न कि एक सीमित स्वामी के रूप में।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा में 'सम्पत्ति' के अंतर्गत ऐसी चल और अचल संपत्ति भी है जो किसी हिंदू स्त्री द्वारा उत्तराधिकार या युक्ति द्वारा, या किसी विभाजन पर, या भरण-पोषण या भरण-पोषण के बकाये के बदले में, या किसी व्यक्ति से, चाहे वह रिश्तेदार हो या न हो, विवाह से पहले, विवाह के समय या उसके बाद, या अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद या प्रिस्क्रिप्शन द्वारा, या किसी अन्य तरीके से, और ऐसी कोई संपत्ति भी है जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारण की गई थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात उपहार के रूप में या वसीयत या किसी अन्य लिखत के अधीन या सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या किसी अधिनिर्णय के अधीन अर्जित किसी संपत्ति पर लागू नहीं होगी, जहां उपहार, वसीयत या अन्य लिखत या डिक्री, आदेश या पुरस्कार की शर्तें ऐसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति का निर्धारण करती हैं।"

(5) अनिवार्य रूप से इस प्रकार के प्रावधान का अर्थ पूर्व-विद्यमान विधि की पृष्ठभूमि और उन तथ्यों के मैट्रिक्स के आलोक में लगाया जाना चाहिए जिनके कारण इसे अधिनियमित करना आवश्यक था। यहाँ तक कि वंशानुगत रूप से भी, किसी अधिनियम को शून्य में नहीं समझा जाना चाहिए और यह आंशिक रूप से धारा 14 के मामले में है, जिसका मुख्य उद्देश्य उस बिंदु पर तत्कालीन मौजूदा हिंदू कानून की पेचीदगियों को दूर करना और उसमें मौलिक रूप से सुधार करना था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की प्रकृति और विस्तार पर एक विस्तृत शोध प्रबंध शुरू करना न तो संभव है और न ही शायद वांछनीय है। फिर भी, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती कानून के संक्षिप्त संदर्भ के बिना, मामले को सही दृष्टिकोण में नहीं रखा जा सकता है।

(6) यह ध्यान देना पर्याप्त है कि 17 जून, 1956 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की उद्घोषणा से पहले, एक हिंदू महिला के संपत्ति के स्वामित्व को उसके अधिकार के अधिकार पर जटिल सीमाओं द्वारा संरक्षित किया गया था, दोनों अधिनियमों द्वारा और उसी के संबंध में उसकी वसीयती शक्तियों के संबंध में भी। विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि स्ट्रिधन की तत्कालीन मौजूदा अवधारणाओं ने इस बिंदु पर सिद्धांत की इतनी बड़ी विविधता का प्रदर्शन किया कि हिंदू कानून के विभिन्न नियमों के तहत सटीक कानूनी स्थिति का अनुमान लगाना कोई आसान काम नहीं था। प्राचीन ग्रंथों ने बिना किसी व्यापक परिभाषा के

स्ट्रिधन के विभिन्न शीर्षों की गणना करने का प्रयास किया, और सम्मान के साथ यह कहा जा सकता है कि बाद के टिप्पणीकारों ने किसी भी तरह से इस मुद्दे पर कानून की स्पष्टता या एकरूपता को नहीं जोड़ा। न केवल यह बल्कि एक महिला के स्वामित्व अधिकारों पर हिंदू कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध दोनों के संबंध में स्त्रीधन और अन्य प्रो पार्टी को उसकी स्थिति से और जटिल कर दिया गया था, i.e, चाहे वह एक युवती, एक विवाहित महिला, या विधवा के रूप में ऐसी संपत्ति में आई हो। इसके अलावा, ऐसी संपत्ति के स्रोत और प्रकृति के आधार पर और जटिलताएं पैदा हुईं। पुनः, स्त्रीधन के उत्तराधिकार का क्रम एक पुरुष मालिक की संपत्ति के मामले में अलग था और यह हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों के तहत आगे भिन्न था। इन सभी कारकों ने कानून की इस शाखा को सबसे जटिल और अपनी तरह का सबसे कम अनुमानित बना दिया।

(7) जैसा कि शायद सर्वविदित है, पचास के दशक के प्रारंभ में संसद ने हिंदू कानून की अंतहीन अवधारणाओं को सरल बनाने और उन्हें संहिताबद्ध करने की भव्य योजना पर जोर दिया। हालांकि, यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। हिंदू संहिता विधेयक, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित किया गया था, पूरी तरह से कानून की पुस्तक में अपना रास्ता नहीं खोज पाया, और विवाह, उत्तराधिकार, अल्पसंख्यक और संरक्षकता, और गोद लेने और रखरखाव के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अलग-अलग अधिनियमों को लागू किया गया। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि हिंदू संहिता विधेयक, 1948 का खंड 91, जो वर्तमान धारा 14 का अग्रदूत था, मूल रूप से निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया गया थाः -

"91. महिला की संपत्ति की प्रकृति-(1) इस संहिता के प्रारंभ के बाद किसी महिला द्वारा अर्जित कोई भी संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति होगी।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी महिला द्वारा उपहार के रूप में या वसीयत के तहत अर्जित किसी संपत्ति पर लागू नहीं होगी, जहां उपहार या वसीयत की शर्तें, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, ऐसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करती हैंः

बशर्ते कि ऐसा कोई निहितार्थ केवल उसके लिंग के कारण उत्पन्न नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा में 'संपत्ति' में किसी महिला द्वारा अर्जित चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं, चाहे वह अधिग्रहण विवाह से पहले, विवाह के बाद या विधवा होने के दौरान किया गया था और क्या विरासत या योजना या विभाजन पर, या रखरखाव या रखरखाव के बकाया के बदले में, या किसी व्यक्ति से उपहार द्वारा, चाहे वह रिश्तेदार हो या न हो, या अपने कौशल या परिश्रम से या किसी अन्य तरीके से खरीद या पर्चे या पर्चे द्वारा किया गया था। "

उपर्युक्त प्रावधान (अन्य के साथ) हिंदू सफलता अधिनियम, 1956 की वर्तमान धारा 14 के रूप में अंतिम रूप से उभरने के लिए कई चयन समितियों और संसदीय बहसों के माध्यम से पारित किया गया, जो ऊपर उद्धृत किया गया है। इसकी सरल भाषा इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि धारा 14 में नियम को शामिल करने में विधायिका का समग्र इरादा हिंदू कानून के कड़े प्रावधानों को निरस्त करना था जो एक महिला मालिक के पूर्ण स्वामित्व अधिकारों के खिलाफ था और उसे एक स्वतंत्र और संपत्ति के पूर्ण मालिक का दर्जा प्रदान करना था। अधिनियम की धारा 14 को लागू करने में इसकी पृष्ठभूमि और इसके निर्माताओं के व्यापक इरादे के लिए इतना।

(8) हमारे समक्ष तर्क अनिवार्य रूप से धारा 14 के उपखंड (1) की भाषा के इर्द-गिर्द केंद्रित है। इसके निर्माण के बड़े मुद्दे पर पक्षों की ओर से लिए गए रुख पर शुरुआत में ही ध्यान देना शायद सबसे अच्छा है। इसमें, अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. मित्तल द्वारा प्रस्तुत तर्क का मूल यह है कि खंड के अंत में "सीमित स्वामी" शब्दों को हिंदू कानून में हिंदू महिला की संपत्ति की प्रसिद्ध अवधारणा के बराबर या अनुरूप नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत तर्क यह है कि "सीमित मालिक" शब्दों को उनके सामान्य और सामान्य अर्थों में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए जिसका अलगाव का अधिकार या तो किसी दस्तावेज़ की स्पष्ट शर्तों या कानून और रीति-रिवाजों के नियमों से बंधा हुआ है। श्री मित्तल का तर्क है कि "सीमित मालिक" शब्दों का उपयोग निर्माताओं द्वारा प्रत्येक हिंदू महिला के सीमित हित को बढ़ाने के लिए अपनी विरासत को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था, न कि केवल पूर्ण स्वामित्व में विस्तार करने के लिए जिसे हिंदू महिला की संपत्ति के रूप में जाना जाता है।

(9) दूसरी ओर, श्री अशोक भान का जोरदार तर्क था कि धारा 14 (1) को इसके इतिहास और पृष्ठभूमि से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए और यहां "सीमित मालिक" शब्द पहले से मौजूद कानून के लिए ज्ञात हिंदू महिला की संपत्ति की प्रकृति की प्रसिद्ध अवधारणा से अपना रंग लेना चाहिए। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ने कहा कि "सीमित मालिक" शब्दों का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाना था क्योंकि विरासत न केवल हिंदू महिला की संपत्ति के रूप में जानी जाती है, बल्कि हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों द्वारा लगाए गए स्त्रीधन के हस्तांतरण पर सभी बंधनों को हटाने के लिए भी था। यह इंगित किया गया था कि विद्यमान कानून द्वारा एक हिंदू महिला के संपत्ति रखने के अधिकार पर रखी गई सीमाओं की विविधता और जटिलता इतनी विशाल और वर्गीकरण के लिए कठिन थी कि विधायिका अनिवार्य रूप से व्यापक शब्दावली का उपयोग करने के लिए मजबूर थी। फिर भी, प्रत्यर्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि इरादा हिंदू महिला से प्राप्त संपत्ति के प्रत्येक विदेशी को पूर्ण स्वामित्व का लाभ प्रदान करने का था और कभी नहीं हो सकता था, लेकिन पहले के कानून के तहत हिंदू महिलाओं द्वारा इस तरह के सीमित स्वामित्व की अच्छी तरह से समझी गई अवधारणाओं को बढ़ाने तक ही सीमित था।

(10) पक्षकारों के बुनियादी रुख को ध्यान में रखते हुए, अब मैं दोनों पक्षों में से किसी एक के आधार पर दिए गए विभिन्न तर्कों की विस्तार से जांच करने का प्रस्ताव करता हूं। अपीलार्थी की ओर से तर्कों के मुख्य आधार को अधिनियम की धारा 14 के उपखंड (1) के स्पष्टीकरण की व्यापक भाषा पर आधारित करने का अनुरोध किया गया था। श्री मित्तल ने तर्क दिया था कि स्पष्टीकरण की शर्तों का व्यापक विस्तार एक हिंदू महिला के हर संभावित प्रकार के सीमित स्वामित्व को कहीं भी और चाहे जो भी मौजूद हो, बढ़ाने के लिए विधायिका के इरादे का एक स्पष्ट संकेत था। रिलायंस को स्पष्टीकरण के व्यक्तिगत खंडों पर यह दिखाने के प्रयास में रखा गया था कि ये आवश्यक रूप से हिंदू कानून की ज्ञात अवधारणाओं को संदर्भित नहीं करते थे, लेकिन इसका उद्देश्य इसके बावजूद पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना था।

(11) इसमें हिंदू सफलता अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों पर निर्भरता रखी गई थी -

"या किसी व्यक्ति से उपहार के रूप में, चाहे वह रिश्तेदार हो या नहीं, उसके विवाह से पहले, उसके समय या उसके बाद",

वकील ने तर्क दिया कि यह सजा हिंदू महिला के जीवन के किसी भी और हर चरण में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी उपहारों को कवर करने के लिए थी। उनके अनुसार, ये शब्द एक समावेशी स्वभाव के थे और इनका उद्देश्य शादी के समय प्राप्त उपहारों को उनके दायरे में लाना था या उनके करीब लाना था। यह तर्क

दिया गया था कि निर्माता इस प्रकार अन्य उपहारों को बाहर नहीं करना चाहते थे जो विवाह समारोह से पूरी तरह से असंबंधित हो सकते हैं। इस तथ्य पर भी कुछ जोर दिया गया था कि यहाँ न केवल रक्त संबंधों से उपहारों का संदर्भ दिया गया है, बल्कि रैंक अजनबियों से भी उपहार दिए गए हैं क्योंकि भाषा स्पष्ट रूप से 'किसी भी व्यक्ति' से उपहारों को संदर्भित करती है।

(12) उपरोक्त सामग्री की सतही संभाव्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है जब विवाह के समय या उसके बारे में दुल्हन को दिए गए उपहारों के विशेष संदर्भ में स्त्रीधन की प्रसिद्ध अवधारणा और उससे संबंधित अन्य उपहारों का संदर्भ दिया जाता है। एक हिंदू महिला को उसके स्त्रीधन से दिए गए कुछ प्रकार के उपहार गंभीर विवाद का विषय नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में सबसे पहले हिंदू कानून के सिद्धांतों पर मुल्ल के आधिकारिक कार्य के पैरा 113 का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि स्मृति के अनुसार भी मनु ने छह प्रकार के स्त्रिधानों की गणना की थी। दुल्हन के जुलूस में शादी की आग (अध्यायनी) से पहले किए गए इन उपहारों, यानी, जब दुल्हन को उसके माता-पिता (अध्यायिका) के घर से उसके पति के घर ले जाया जा रहा है, तो दुल्हन के ससुर और सास द्वारा प्यार के प्रतीक में बनाए गए उपहार और उसके बड़ों (पदवंदनिका) के चरणों में मत्था टेकने के समय भी बनाए गए उपहार। इन तीन प्रकार के उपहारों के अलावा, जो स्पष्ट रूप से विवाह समारोह से निकटता से संबंधित थे, मनु द्वारा विशेष रूप से पिता, माँ या भाई द्वारा बनाए गए उपहारों का भी उल्लेख किया गया है। हालाँकि, हिंदू दुल्हन या एक हिंदू महिला को इस तरह के उपहार जो प्राचीन काल से उनकी स्त्रीधन माने जाते थे, किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं थे। यहाँ तक कि विष्णु जैसे सापेक्ष रूप से प्राचीन टीकाकार ने भी इसमें जोड़ा कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी (अधिवेदानिका) को सुपर-सेशन पर दिए गए उपहारों का उल्लेख करते हुए, अर्थात्, उसकी दूसरी पत्नी (अधिवेदानिका) लेने के अवसर पर उसके पति के रिश्तेदारों या उसके माता-पिता के रिश्तेदारों (अन्वेषक) द्वारा शादी के बाद दिए गए उपहार सुल्का या विवाह-शुल्क (एक शब्द जो बल्कि लोचदार है और हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों में अलग-अलग अर्थों में उपयोग किया जाता है) और अंत में बेटों और रिश्तेदारों से उपहार।

(13) अब एक हिंदू महिला के उपरोक्त उपहारों को रखने और निपटाने के अधिकार की प्रकृति और सीमा, जो निस्संदेह स्त्रीधन थे, हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों में व्यापक रूप से भिन्न थी। शायद हमारे उद्देश्य के लिए इन नियमों के विचलन को किसी भी विस्तार से नोटिस करना अनावश्यक है और यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि मिताक्षर और दयाभाग के साथ-साथ बॉम्बे, बनारस, मद्रास और मिथिला हिंदू कानून के स्कूल एक-दूसरे से अलग थे। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ये परिवर्तन न केवल ऐसे स्त्रीधन के धारण और निपटान के अधिकार से संबंधित थे, बल्कि उत्तराधिकार के तरीके और तरीके के संबंध में भी थे। विवाह के समय या उसके आसपास के उपहारों के अलावा, हिंदू कानून के नियमों ने एक हिंदू महिला के साथ संबंधों द्वारा दिए गए उपहारों और वसीयतों के संबंध में समान विविधता दिखाई। इस संदर्भ में मुल्ला के हिंदू कानून के पैरा 126 को उद्धृत करना पर्याप्त हैः -

"126. संबंधों से उपहार और वसीयतः

हिंदू स्त्री को उसके माता-पिता और उनके रिश्तेदारों द्वारा, या उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा, चाहे वह प्रसव के दौरान हो या विधवा होने के दौरान, दी गई या वसीयत की गई संपत्ति सभी स्कूलों के अनुसार स्त्रीधन है, सिवाय इसके कि दयाभाग किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को दी गई या वसीयत की गई अचल संपत्ति को स्त्रीधन के रूप में मान्यता नहीं देता है। "

इसी तरह कानून के विस्तृत और जटिल नियम अजनबियों द्वारा एक हिंदू महिला को दिए गए उपहारों और वसीयतों के क्षेत्र में संचालित होते थे। मुल्ला ने इसे पैरा 127 में इस प्रकार नोट किया हैः -

"127. अजनबियों से उपहार और वसीयतः

एक हिंदू महिला द्वारा एक अजनबी से उपहार प्राप्त किया जा सकता है, यानी उस व्यक्ति से जो संबंध नहीं है (1) मातृत्व के दौरान या (2) विवाह के समय, या (3) डक्सिंग कवरचर या (4) विधवा के दौरान। "

(14) यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक हिंदू महिला की गुप्तता के दौरान स्त्रीधन का निपटान करने की शक्ति आगे स्त्रीधन के चरित्र पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य के लिए, स्ट्रिधन को फिर से दो वर्गों में विभाजित किया गया, अर्थात्, सौदयिका और गैर-सौदयिका। जहां तक विधवा होने के दौरान स्त्रीधन पर अधिकारों का संबंध है, एक हिंदू महिला को विधवा होने के दौरान किसी भी प्रकार के स्त्रीधन पर निपटान की पूर्ण शक्ति थी, चाहे वह उसके पति की मृत्यु से पहले या बाद में अर्जित की गई हो।

(15) उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण में हिंदू स्त्री को दिए गए उपहारों से संबंधित पूर्व-उद्धृत वाक्य स्पष्ट रूप से हिंदू कानून में ऐसे उपहारों से संबंधित स्त्रीधन की प्रसिद्ध अवधारणाओं से जुड़ा और संबंधित था। इसलिए, निर्माताओं का इरादा ऐसे उपहारों में एक हिंदू महिला की संपत्ति की रोशनी को पूर्ण स्वामित्व में बढ़ाना और ऐसे उपहारों पर हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों द्वारा लगाए गए बंधनों को स्पष्ट रूप से हटाना प्रतीत होता है। इसमें प्रयुक्त भाषा का अर्थ केवल पृथक रूप में नहीं बल्कि धारा 14 के अधिनियमन के समय पूर्व-विद्यमान हिंदू विधि के विशेष संदर्भ में किया जाना है। इस खंड को अन्यथा पढ़ना, जैसे कि एक निर्वात में, मेरे विचार में शायद ही उचित होगा।

(16) स्पष्टीकरण में अन्य शब्दों और वाक्यों पर वकील की निर्भरता कमोबेश समान महत्व की थी। इन पर अब सापेक्ष संक्षिप्तता में विचार किया जा सकता है और उनसे निपटा जा सकता है। श्री मित्तल ने यह तर्क देने के लिए स्पष्टीकरण में उपयोग किए गए शब्दों "या अपने स्वयं के कौशल या परिश्रम से" का उल्लेख किया कि ऐसी संपत्ति स्पष्ट रूप से एक हिंदू महिला का पूर्ण अधिकार है और इसलिए, इन शब्दों की इस मुद्दे पर पहले के हिंदू कानून के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है।

(17) इस विवाद की भ्रांति तब स्पष्ट हो जाएगी जब मुल्ला के हिंदू कानून के पैरा 131 का संदर्भ दिया जाएगा। यह एक हिंदू महिला द्वारा भौतिक कलाओं द्वारा या अन्यथा अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा प्राप्त संपत्ति पर लागू नियमों को चित्रित करता है। इस तरह की संपत्ति को स्पष्ट रूप से हिंदू कानून के अधिकांश स्कूलों द्वारा स्त्रीधन माना गया था, लेकिन यहां भी कोई पूर्ण सर्वसम्मति नहीं थी। एक महिला द्वारा अपने स्वयं के कौशल या परिश्रम से अर्जित इस संपत्ति के संबंध में स्वामित्व के अधिकार की प्रकृति फिर से विभिन्न स्कूलों के अनुसार भिन्न थी। जबकि बॉम्बे, बनारस और मद्रास स्कूलों के अनुसार गुप्तता के दौरान अर्जित ऐसी संपत्ति स्त्रीधन थी, मिथिला और दयाबाघा स्कूलों के अनुसार ऐसा नहीं था। आम तौर पर, एक हिंदू महिला द्वारा अपने स्वयं के परिश्रम से अर्जित संपत्ति उसकी स्त्रीधन थी, यदि ऐसा मातृत्व या विधवापन के दौरान अर्जित किया गया था। ऐसी संपत्ति पर लागू कानून के नियमों के विचलन का विस्तृत संदर्भ देना अनावश्यक है। यह कहना पर्याप्त है कि एक हिंदू महिला द्वारा अपने कौशल या परिश्रम से अर्जित संपत्ति के संदर्भ में अपवाद में उल्लेख भी एक हिंदू महिला के हाथों में ऐसी संपत्ति से संबंधित हिंदू कानून के प्रारंभिक नियमों में निहित था और प्रासंगिक था। यहाँ फिर से इरादा ऐसी संपत्ति पर पहले से मौजूद कानून द्वारा लगाई गई सीमाओं के विपरीत स्थायी स्वामित्व प्रदान करना प्रतीत होता है।

(18) स्पष्टीकरण के प्रत्येक वाक्य या खंड के लिए व्यक्तिगत रूप से विज्ञापन करना शायद व्यर्थ होगा, जिसके लिए अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा कुछ संदर्भ दिया गया था। यह वास्तव में शब्दों पर उनकी अंतिम निर्भरता का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है "या किसी अन्य तरीके से जो भी इसके अंतिम भाग में उपयोग किया गया है। इस शब्दावली के बल पर वकील ने तर्क दिया कि इन व्यापक शब्दों की पहले के हिंदू कानून के साथ बहुत कम या कोई प्रासंगिकता नहीं है और यह एक हिंदू महिला के हाथों में किसी भी और हर प्रकार की संपत्ति के विस्तार को शामिल करेगा।

(19) जब मुल्ला के हिंदू कानून के पैरा 135 का संदर्भ दिया जाता है तो उपरोक्त विवाद को फिर से नकार दिया जाता है। यह एक हिंदू महिला की ऐसी संपत्ति से संबंधित है जिसे स्त्रीधन के प्रमुख स्रोतों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। मुल्ला ने आधिकारिक रूप से उल्लेख किया है कि क्या किसी अन्य स्रोत से उसके द्वारा अर्जित ऐसी संपत्ति उसकी स्त्रीधन का गठन करती है या नहीं, यह पहले पैरा 123 में उल्लिखित हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों के विस्तृत नियमों को लागू करके निर्धारित किया जाना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब स्पष्टीकरण के निर्माताओं ने एक हिंदू महिला द्वारा किसी अन्य तरीके से अर्जित संपत्ति का उल्लेख किया, तो उनके दिमाग में मूल और स्पष्ट रूप से गणना किए गए स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से स्त्रीधन की ज्ञात अवधारणा थी। यहाँ फिर से अंतिम परिणाम यह था कि पहले से मौजूद हिंदू कानून के तहत सीमित स्वामित्व के विपरीत पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया जाए।

(20) वास्तव में मुझे यह प्रतीत होता है कि भाषा पर निर्भरता। स्पष्टीकरण के विभिन्न खंड अंततः अपीलार्थी की ओर से प्रचार किए गए निर्माण पर बूमरैंग करते हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री अशोक भान ने अपने उत्तर में वास्तव में जवाबी हमला किया और स्वयं इस स्पष्टीकरण की भाषा पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि उसमें उल्लिखित संपत्ति की विभिन्न गणनाएँ पहले से मौजूद हिंदू कानून में स्त्रीधन की धारणा से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि इस भाषा को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और न ही पढ़ा जाना चाहिए और उन्होंने इसकी मूल पृष्ठभूमि से तलाक ले लिया। यह इंगित किया गया था कि मोटे तौर पर इसमें उपयोग की जाने वाली भाषा में मुख्य रूप से कला के शब्द शामिल थे, जिसमें एक हिंदू महिला के स्त्रीधन संपत्ति के संबंध में सीमित स्वामित्व की विशिष्ट घटना का विशेष संदर्भ था।

(21) उपर्युक्त विवाद के समर्थन में और उसके उदाहरण के रूप में। उन्होंने सबसे पहले 'विरासत या योजना' शब्दों की ओर इशारा किया, जो उनके अनुसार, मुल्ला के हिंदू कानून के पैरा 130 में निर्दिष्ट विरासत द्वारा अर्जित एक हिंदू महिला की स्त्रीधन संपत्ति से स्पष्ट रूप से संबंधित होंगे। यह उन दो मामलों को अलग करता है जहां एक महिला को एक पुरुष की सामान्य संपत्ति विरासत में मिलती है जैसे कि उसका पति, पिता या पुत्र, जबकि स्त्री की स्त्रीधन की विरासत जैसे कि उसकी माँ, बेटी और बाकी। दयाभागा स्कूल के साथ-साथ बनारस, मिथिला और मद्रास स्कूल के अनुसार, एक महिला को विरासत में मिली संपत्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसकी स्त्रीधन नहीं बनती है और वह संपत्ति में केवल सीमित रुचि लेती है। वह वंश का एक नया समूह नहीं बन जाती है और उसकी मृत्यु पर उपरोक्त संपत्ति उसके अपने उत्तराधिकारियों को नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के अगले उत्तराधिकारियों को दी जाएगी जिनसे वह विरासत में मिली थी। हालाँकि, इसके विपरीत, मिताक्षर और बॉम्बे स्कूलों में अलग-अलग नियम लागू थे। इस प्रकार श्री अशोक भान के तर्क में बल प्रतीत होता है कि यह मुख्य रूप से उपरोक्त प्रकार की संपत्ति के लिए था जिसका संदर्भ 'विरासत या योजना' शब्दों के उपयोग द्वारा स्पष्टीकरण में दिया गया था।

(22) इसी प्रकार 'या विभाजन के समय' शब्दों को मुल्ला के हिंदू कानून के पैरा 128 से सह-संबंधित किया गया है, जो वैध नियमों को निर्दिष्ट करता है, जब किसी माता या पिता की माता को संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन पर कोई हिस्सा आवंटित किया जाता है या यह उसे उसके रखरखाव के प्रावधान के रूप में दिया जाता है, जिसके लिए परिवार की संपत्ति बाध्य है। पुनः 'भरण-पोषण या भरण-पोषण के बकाये के बदले में' वाक्यांश को मुल्ला के हिंदू कानून के पैरा 129 में कानून के कथन से जोड़ा गया है। 'क्रय द्वारा या पर्चे द्वारा' के संदर्भ को इसी तरह हिंदू कानून की घटनाओं के संबंध में स्ट्रिधन के साथ खरीदी गई संपत्ति और एक हिंदू महिला द्वारा प्रतिकूल कब्जे या पर्चे द्वारा प्राप्त संपत्ति के संबंध में जोड़ा गया है, जो क्रमशः मुल्ला के काम के पैरा 134 और 133 में वर्णित हैं।

(23) अंत में, इस संदर्भ में, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने स्पष्टीकरण के समापन वाक्य का उल्लेख किया-"और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारण की गई कोई भी संपत्ति"। यह प्रस्तुत किया गया था कि इसका पूर्ववर्ती भाषा के साथ एक अभिन्न संबंध था और इसका उपयोग एक अवशिष्ट खंड के रूप में किया गया था ताकि इसके दायरे में सभी प्रकार के स्ट्रिधन को शामिल किया जा सके जो या तो पहले गणना से चूक गए हों या स्पष्टीकरण के पहले भाग में खंडों के दायरे में सख्ती से नहीं आते हों।

(24) मेरा विचार है कि यहाँ स्पष्टीकरण का अर्थ लगाने में हेडन के मामले में निर्धारित पवित्र नियम का पालन करना चाहिए। इसलिए वास्तव में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लागू करने से पहले कानून की स्थिति क्या थी, उस कानून में क्या शरारत या दोष था जिसके लिए संसद द्वारा उपाय प्रदान किया जा रहा था और उस उपाय के कारण क्या थे। निर्माण के इस सिद्धांत की हाल ही में पुष्टि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा ब्लैक-क्लॉसन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम पापियनवेर्के वाल्डोफ़-एशफ़ेनबर्ग एजी में की गई है।

(25) इस प्रकार देखे जाने पर यह प्रतीत होता है कि यद्यपि प्रथमतः स्पष्टीकरण की भाषा पर अपीलार्थी के विद्वत वकील का तर्क सरल प्रतीत होता है, फिर भी धारा 14 (1) को अधिनियमित करते समय पूर्व-विद्यमान हिंदू विधि की उचित पृष्ठभूमि के विरुद्ध गहराई से किया गया विश्लेषण अंततः अपीलार्थी की ओर से लिए गए रुख से गंभीर रूप से विमुख हो जाता है।

(26) पारित करते समय कोई भी अपीलार्थी के विद्वत वकील के इस तर्क का विज्ञापन कर सकता है कि यदि विधि का आशय केवल हिंदू महिला संपदा की ज्ञात अवधारणाओं के विस्तार तक ही सीमित था, तो मसौदा तैयार करने वालों ने 'सीमित स्वामी' शब्दों के बजाय धारा 14 (1) के अंतिम भाग में उन्हीं शब्दों का उपयोग किया होगा, जिनका अधिक व्यापक अर्थ है। हालाँकि, यह तर्क इस तथ्य को भूलता प्रतीत होता है कि हिंदू कानून में संपत्ति की कई अवधारणाओं के अलावा, पहले के कानून में एक हिंदू महिला की संपत्ति दो व्यापक श्रेणियों में आती थी, अर्थात्, अपनी ज्ञात सीमाओं के साथ एक हिंदू महिला की संपत्ति, और जिसे सख्ती से स्त्रीधन कहा जाता था, जो अपने स्वयं के विशेष नियमों द्वारा शासित था। धारा 14 के तहत कानून का बड़ा इरादा हिंदू महिला संपदा के रूप में आयोजित संपत्ति का विस्तार करना था और एक महिला की स्त्रीधन संपत्ति पर लगाए गए जटिल बंधनों को भी हटाना और निरस्त करना था। ऐसा लगता है कि इन दोनों मामलों में संपत्ति के एक स्वतंत्र और पूर्ण मालिक के रूप में उसकी स्थिति को पहचानना उद्देश्य प्रतीत होता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मसौदा तैयार करने वाले संभवतः केवल धारा 14 (1) में 'हिंदू महिला संपदा' वाक्यांश का उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका उद्देश्य न केवल एक बल्कि अन्य प्रकार के सीमित मालिकों को भी पूर्ण स्वामित्व में बढ़ाना था। इसलिए, विधानमंडल द्वारा

किस भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, इस बारे में अपीलार्थी के अंतिम विवाद के लिए विद्वान वकील में बहुत अधिक सार नहीं प्रतीत होता है।

(27) अब इसमें अपीलार्थी एक सीमित महिला स्वामी से मात्र पराई है, जिससे उसने एक पूर्ण उपहार प्राप्त करने का आशय किया था (हालांकि स्वीकार किया कि दाता को इसे बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ से पहले इसका कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसलिए, मामले का मूल यह है कि क्या धारा 14 का उद्देश्य केवल एक महिला सीमित मालिक के विदेशी को लाभ पहुंचाना था। अपीलार्थी की ओर से यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि ऐसे प्रत्ययी या अंतरिती भी धारा 14 के दायरे में थे, जबकि प्रत्यर्थी की ओर से जोरदार तर्क यह था कि उद्देश्य केवल उन महिला हिंदुओं को लाभान्वित करने तक सीमित था जो तत्कालीन मौजूदा हिंदू कानून के अनुसार सीमित मालिक थीं।

(28) यहां तक कि एक क्षण के लिए (ऐसा माने बिना) यह मानते हुए कि धारा 14 की भाषा पर दो निर्माण संभव हैं, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के आधे हिस्से पर क़ानून पर रखी जाने वाली व्याख्या तीन पेटेंट विसंगतियों का कारण बनेगी।

(29) सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ से पहले एक पुरुष दाता के पक्ष में एक महिला लिमिटेड मालिक द्वारा किए जाने वाले एक पूर्ण उपहार का मामला ले सकता है। कानून की भाषा पर ही यह स्पष्ट है कि इस तरह के उपहार को संभवतः धारा 14 (1) के आधार पर एक पुरुष दाता के हाथों में एक पूर्ण उपहार में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। यह अपीलार्थी की ओर से श्री मित्तल द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया था।इस स्थिति का स्पष्ट परिणाम यह होगा कि यदि एक ही सीमित महिला स्वामी समान संपत्ति के एक ही समय में दो उपहार देता है, एक महिला को और दूसरा पुरुष को, अधिनियम के प्रवर्तन से पहले, महिला के पक्ष में उपहार अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार पूर्ण स्वामित्व में विस्तारित हो जाएगा, जबकि पुरुष के पक्ष में ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है। दबाए जाने पर भी विद्वान वकील तथ्यों के एक समान समूह पर कानून में उत्पन्न होने वाले ऐसे अलग-अलग और विरोधाभासी परिणामों के लिए कोई तर्क देने में असमर्थ था।

(30) दूसरा, इसके विपरीत, एक पुरुष सीमित मालिक द्वारा एक महिला हिंदू के पक्ष में एक उपहार के उदाहरण को ध्यान में रखा जा सकता है, जिसे अधिनियम के लागू होने से पहले उसके कब्जे में रखा गया है। अपीलार्थी की ओर से प्रचार किए गए निर्माण पर, और भी अधिक चौंका देने वाले परिणाम सामने आएंगे। उनके अनुसार, ऐसा उपहार फिर से धारा 14 (1) के दायरे में आएगा और संपत्ति का विस्तार महिला दाता के हाथों में पूर्ण स्वामित्व में हो जाएगा। अब यह स्पष्ट है कि यदि वही संपत्ति मूल दाता, जो स्वयं एक सीमित स्वामी था, के पास बनी रहती, तो संभवतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के किसी भी प्रावधान से उसे ऐसा कोई लाभकारी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता था। क्या यह कल्पना करना संभव होगा कि संपत्ति का अधिकार जो अनिवार्य रूप से मूल पुरुष हिंदू मालिक के हाथों में सीमित प्रकृति का था, केवल एक महिला को हस्तांतरित करने की घटना से एक पूर्ण प्रकृति का हो जाएगा? यह अकल्पनीय प्रतीत होता है कि विधानमंडल का आशय यह था कि एक हिंदू पुरुष के हाथों में सीमित स्वामित्व की ज्ञात घटनाओं को एक महिला के पक्ष में अलगाव द्वारा पूर्ण स्वामित्व में विस्तारित किया जाना चाहिए, जिसे कब्जे में रखा गया है। इसके अलावा, पिछले उदाहरण में विरोधाभास देखा गया! इस संदर्भ में भी खुद को दोहराएंगे i.e. जहाँ दान स्त्री को दिया जाता है, जबकि दान पुरुष को दिया जाता है।

(31) तीसरा, कोई व्यक्ति मरुदक्कुल में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए चित्रण (उपयुक्त संशोधन के साथ) की अनुदेशात्मक रूप से जांच कर सकता है और दूसरा बनाम अरुमुघा गौंडर, ए.आई.आर 1958 मद्रास 255: एक हिंदू महिला, अधिनियम के लागू होने से पहले, अपने पति से एक लाख रुपये की अचल संपत्ति विरासत में प्राप्त करती है। वह इसका प्रबंधन करना मुश्किल समझती है और संपत्ति को नकद में बदल देती है और इसे बिना किसी कानूनी आवश्यकता के एक महिला विदेशी को बेच देती है जो जानबूझकर इसे केवल तीस हजार रुपये के सकल कम मूल्यांकन मूल्य पर खरीदती है और उसी पर कब्जा कर लेती है। यह कहना कि धारा 14 (1) का प्रभाव ऐसे परदेसी को संपत्ति का पूर्ण स्वामी बनाना होगा, यह अभिनिर्धारित करने के समान होगा कि संसद ने एक बेईमान परदेसी को भी अपने इनाम के विषय के रूप में बनाने का इरादा किया था। क्या यह कहा जा सकता है कि विधायिका का इरादा संपत्ति के वास्तविक और कम मूल्यांकन मूल्य के बीच के अंतर को एक सांठगांठ वाले विदेशी को उपहार में देना होगा, जिसने अपनी आँखें खुली रखते हुए कानूनी आवश्यकता के अभाव में हस्तांतरण की उसकी शक्ति पर ज्ञात सीमाओं के साथ एक सीमित महिला मालिक की संपत्ति खरीदी थी?

(32) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से प्रचार किया गया निर्माण एक नहीं बल्कि कई प्रतिकूल परिणामों की ओर ले जाता है। यह निर्माण का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्याख्या से बचा जाना चाहिए जो इसके सामने तर्कहीन परिणामों की ओर ले जाती है। धारा 14 (1) की भाषा ऐसी प्रकृति की नहीं है जो केवल एक निर्माण से संभव हो। इसलिए, जहां स्पष्ट रूप से दो निर्माण संभव हैं, तो किसी को स्पष्ट रूप से उस पर झुकना चाहिए जो तर्कहीन और असमर्थनीय परिणामों से बचता है।

(33) धारा 14 (1) की भाषा की ओर लौटते हुए यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह एक महिला हिंदू द्वारा संपत्ति के कब्जे को, चाहे वह वास्तविक हो या रचनात्मक, पहले से ही महत्वपूर्ण महत्व देता है, ताकि सीमित ब्याज के पूर्ण ब्याज में विस्तार के लाभ को सुरक्षित किया जा सके। इस प्रकार कानून के तहत संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने से पहले कब्जा एक अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार, धारा 14 (1) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए सीमित हित और संपत्ति के कब्जे दोनों को सहमत होना होगा। यह स्थिति गंभीर संदेह में नहीं है और इस मुद्दे पर कई अधिकारियों का संदर्भ अनावश्यक है क्योंकि अपीलार्थी की ओर से श्री मित्तल ने इस तथ्य को उचित रूप से स्वीकार किया है। इसलिए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि एक सीमित 'महिला हिंदू स्वामी ने संपत्ति का कब्जा खो दिया है या छोड़ दिया है' तो वह स्वयं उपरोक्त प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकती है। ऐसा होने पर, क्या यह तर्कसंगत होगा कि एक मात्र अंतरिती या विदेशी जो एक महिला है और जिसने स्वयं कभी भी हिंदू कानून के तहत सीमित स्वामित्व की आवश्यक घटना के साथ संपत्ति नहीं रखी है, वह इस तरह के लाभ को प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए? इसलिए, अपीलार्थी की ओर से प्रचार किए गए निर्माण में यह भ्रम शामिल प्रतीत होता है कि भले ही मूल महिला सीमित मालिक एक बार उसके कब्जे से बाहर हो जाने के बाद उसके ब्याज में कोई वृद्धि सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगी, फिर भी एक मात्र खरीदार, एक बंधक या उससे कोई अन्य महिला विदेशी, फिर भी, इस तरह के लाभ का हकदार होगा। मेरे विचार से यह तर्क के सादे आदेशों को संतुष्ट नहीं करता है। कोई भी आसानी से ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकता है जो असामान्य घटना की न हो, जहां मूल महिला सीमित मालिक और उसके एक या दूसरे उत्तराधिकारी के बीच संपत्ति के विस्तार को सुरक्षित करने के लिए हितों का सीधा टकराव हो सकता है। यह वास्तव में एक अजीब परिणाम होगा कि हालांकि इस तरह का लाभ स्पष्ट रूप से मूल सीमित मालिक को नहीं मिलेगा, फिर भी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना चाहिए जो पूरी तरह से ऐसे विदेशी से अपना खिताब प्राप्त करता है।

(34) व्यापक संभावना में यह स्मरण करने योग्य है कि हिंदू कानून में महिला उत्तराधिकारियों के सीमित स्वामित्व की एक मुख्य अवधारणा यह है कि उनके हाथों में सभ्य और संपत्ति का एक नया स्टॉक नहीं था जो प्रत्यावर्तकों या दूसरे शब्दों में, अंतिम पुरुष धारक के उत्तराधिकारियों को वापस कर दिया गया था। यह तर्क कि महिला विदेशी फिर से विस्तार के लाभ की हकदार होंगी, इस असंगत परिणाम की ओर ले जाता है कि ऐसी संपत्ति न तो महिला सीमित उत्तराधिकारी के पूर्ण स्वामित्व में चली जाती है और न ही यह पूर्ववर्ती पुरुष मालिकों के उत्तराधिकारियों को वापस मिल जाती है, लेकिन एक विदेशी महिला होने की शुद्ध दुर्घटना से, बाद वाला इसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। इस तरह का एक आकस्मिक परिणाम शायद ही विधायिका द्वारा जानबूझकर किया जा सकता था।

(35) अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री मित्तल के प्रति निष्पक्षता में, मुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने घटनाओं और अपने पति से विरासत में मिली संपत्ति में एक हिंदू विधवा के अधिकार की प्रकृति पर बहुत अधिक भरोसा किया। उच्च प्राधिकारी के आधार पर यह तर्क दिया गया था कि जब तक एक हिंदू विधवा जीवित थी, तब तक वह अपने पति की विरासत में मिली संपत्ति का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती थी और उसमें उसके हित को केवल जीवन हित के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था जैसा कि पश्चिमी न्यायशास्त्र में जाना जाता है। यह शायद सच है, लेकिन कोई यह देखने में विफल रहता है कि यह तथ्य किसी भी तरह से मुद्दे के मूल बिंदु से कैसे आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा, अर्थात्, क्या एक महिला सीमित मालिक से मात्र महिला सहायक धारा 14 के तहत संपत्ति के विस्तार के लाभ के हकदार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह धारा केवल हिंदू विधवा की संपत्ति तक ही सीमित नहीं है और यह केवल हिंदू विधवा की संपत्ति तक ही सीमित नहीं है।

इसकी भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है और इसलिए इसमें संपत्ति की सभी महिला मालिक शामिल हैं, न कि केवल विधवाएं। समान रूप से इसकी परिधि के भीतर ऐसी संपत्ति है जो एक स्त्रीधन (हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों के अनुसार उस पर चौड़ी और विविध बंधनों के साथ) के रूप में जानी जाती है, साथ ही एक महिला उत्तराधिकारी द्वारा महिला पूर्ववर्तियों के हित में और पति के अलावा अन्य संबंधों से विरासत में मिली संपत्ति भी है। इसलिए, कानूनी आवश्यकता के मामलों में अलगाव के अधिकार सहित एक हिंदू विधवा की संपत्ति की बहुत ही अजीब घटनाओं पर आधारित होने का अनुरोध किया गया विशिष्ट तर्क (और अन्य निर्दिष्ट स्थितियों में जिसका संदर्भ अनावश्यक है) वर्तमान बिंदु की जांच में कोई बड़ा महत्व नहीं है और वास्तव में यह शायद ही कोई प्रासंगिक लगता है।

(36) मैंने अब तक अपने समक्ष प्रश्न का उसके इतिहास की पृष्ठभूमि में, कानून की भाषा पर और सिद्धांत रूप में भी काफी विस्तार से परीक्षण करने का प्रयास किया है क्योंकि ऊपर वर्णित कुछ पहलुओं पर हमारे सामने उद्धृत मामलों में पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। हालाँकि, अब शेष तर्कों और तर्कों की जांच करना व्यर्थ और शायद विलंबकारी होगा जैसे कि वे पहली छाप के मामले थे, जबकि वास्तव में इसका एक बड़ा क्षेत्र कई उदाहरणों से ढका हुआ प्रतीत होता है। इसलिए, मैं अब इस मुद्दे पर मामले की विधि की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं और भले ही उस बिंदु पर अधिकार का एक महत्वपूर्ण टकराव है, जिसके लिए आगे संदर्भ दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस दृष्टिकोण को लेने के लिए इच्छुक हूं, वह इस न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों दोनों के भीतर अधिकार के असाधारण भार से अच्छी तरह से समर्थित है।

(37) अलग-अलग मामलों की ओर ध्यान देने से पहले, श्री मित्तल की इस व्यापक शिकायत पर ध्यान देना शायद उचित होगा कि उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुकदमा कानून में मुख्य रूप से महिला लिमिटेड के मालिक से पुरुष सहायकों के उदाहरण शामिल थे। उनका निवेदन आगे यह था कि इन मामलों में मामले

की जांच मुख्य रूप से विदेशी या प्रत्यावर्तकों के दृष्टिकोण से की गई थी, न कि किसी महिला विदेशी के दृष्टिकोण से। श्री मित्तल के कथन में कुछ हद तक सच्चाई है क्योंकि मोटे तौर पर हमारे सामने दिए गए निर्णय बड़े पैमाने पर पुरुष हस्तांतरणकर्ताओं या विधवाओं या अन्य महिला लिमिटेड मालिकों के मामलों से संबंधित हैं। फिर भी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद निर्दिष्ट निर्णय का तर्क और तर्क केवल इस कारक से ही विकृत या अप्रयोज्य नहीं होता है। निर्णयों का तर्क आवश्यक रूप से केवल प्राप्तकर्ता या विदेशी के लिंग पर नहीं है, बल्कि विधानमंडल के आशय, क़ानून की भाषा और स्पष्ट रूप से तार्किक निष्कर्ष के सिद्धांतों के व्यापक और बुनियादी विचारों पर आधारित है।

(38) अब, सीधे तौर पर इस मुद्दे से संबंधित कानून का स्पष्ट उच्चारण हरक सिंह बनाम कैलाश सिंह और अन्य, ए.आई.आर 1958 पटना, 581 मामले में पूर्ण पीठ के फैसले में दिखाई देता है। मुख्य न्यायाधीश रामास्वामी ने पीठ की ओर से अनिश्चित शब्दों में बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का अधिनियम XXX) का उद्देश्य हिंदू महिलाओं की कानूनी स्थिति में सुधार करना, विरासत में मिली या उनके द्वारा धारण की गई संपत्ति में उनके सीमित हित को पूर्ण हित तक बढ़ाना था, बशर्ते कि अधिनियम लागू होने पर वे संपत्ति के कब्जे में हों, और इसलिए, इसके लाभकारी प्रावधानों का लाभ उठाने की स्थिति में हों। इस अधिनियम का उद्देश्य निश्चित रूप से गैर-कानूनी लोगों को लाभ पहुंचाना या गैर-कानूनी लोगों को अनुचित रूप से समृद्ध करना नहीं था, जिन्होंने अधिनियम लागू होने से पहले आवश्यकता को उचित ठहराए बिना सीमित मालिकों से संपत्ति खरीदी थी और ऐसे समय में जब विक्रेताओं के पास केवल हिंदू महिलाओं का सीमित हित था। इसलिए, मेरी राय है कि धारा 14 का प्रभाव विदेशी के हित को पूर्ण रूप से अक्षम्य हित में विस्तारित करना नहीं है। धारा 14 की ऐसी व्याख्या को सही नहीं माना जा सकता है। "

यह शायद समान रूप से ध्यान देने योग्य है कि पूर्ण पीठ ने अपने स्वयं के न्यायालय के दो पिछले खंड पीठ के फैसलों को ओवरराइड किया, जो राम अयोध्या मिसिर और अन्य बनाम रघुनाथ मिसिर और अन्य ए.आई.आर 1957 पटना, 480 और माउंट जानकी कुर और अन्य बनाम छठू प्रसाद और अन्य ए.आई.आर 1957 पटना 674 के रूप में रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें इसके विपरीत कुछ टिप्पणियां शायद दिखाई दी थीं।

(39) उपर्युक्त दृष्टिकोण को जल्द ही गुम्मलपुरा तागीना मटाडा कोट्टुरूस्वामी बनाम सत्र वीरव और अन्य ए.आई.आर 1959 एस.सी. 577 में लॉर्डशिप की मंजूरी से पवित्र कर दिया गया था। इसे व्यापक रूप से उद्धृत करना अनावश्यक है और यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि रिपोर्ट के पैरा 10 में इमाम, न्यायमूर्ति ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए पटना डिवीजन पीठों के पिछले दृष्टिकोण के अति-निर्णय को देखा और पूर्व-उद्धृत दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से संदर्भित किया।

(40) इस न्यायालय के भीतर मामले पर अमर सिंह और अन्य बनाम सेवा राम और अन्य (7) में पूर्ण पीठ द्वारा अधिकृत रूप से विचार किया गया है और पीठ ने गुम्मलपुरा तागीना मैया कोट्टुरूस्वामी के मामले (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय के फैसले के तथ्य को भी स्वीकार किया है। हालांकि पूर्ण पीठ के समक्ष प्रश्न थोड़ा अलग था, लेकिन शुरुआत में ही न्यायमूर्ति मेहर सिंह (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने देखा कि मामला काफी हद तक अधिनियम की धारा 14 के विचार और प्रभाव पर आधारित था। यद्यपि एक आनुषंगिक मुद्दे पर कुछ मतभेद था, तथापि पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों के बीच उस मुद्दे पर पूर्ण एकमत प्रतीत होता है जो यहां विचार के लिए आता है जैसा कि दुलत न्यायमूर्ति की निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट होता हैः -

" जहां तक पहले मामले का संबंध है, मुझे मेहर सिंह न्यायमूर्ति ने जो कहा है उससे सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं है, और ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 577 में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को देखते हुए, मेरी राय में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 का उद्देश्य कभी भी हस्तांतरणकर्ताओं को लाभ पहुंचाना नहीं था, एक महिला मालिक जो उस समय उससे संपत्ति खरीदती थी जब उसकी संपत्ति सीमित थी। "

अधिकारियों को गुणा करना अनावश्यक है और यह इस बात के लिए पर्याप्त होगा कि यह दृष्टिकोण कि धारा 14 एक हिंदू महिला के अन्य लोगों के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं करती है, फिर से गद्दाम वेंकैया और अन्य बनाम गद्दाम वीरय्या (मृत) और अन्य एआईआर 1957 आंध्र प्रदेश 280 मरुदक्कल और एक अन्य बनाम अरुमुघा गौंडर (उपरोक्त) और एस कांतिमथिनाथ पिल्लई बनाम वयापुरी मुदलियार एआईआर 1963 मद्रास 37 में अधिकृत रूप से स्पष्ट किया गया है। तथापि, अनाथ बंधु सेन मंडल बनाम चंचला बाला दासी 80 कलकत्ता साप्ताहिक नोट्स 461 मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की हाल की खंड पीठ के निर्णय का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें, चिन्टी बनाम डाल्टी एआईआर 1968 दिल्ली 264, में विसंगत दृष्टिकोण सहित मामले की विधि की विस्तृत चर्चा के बाद यह पाया गयाः -

" ऊपर उल्लिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव और कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित कई उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और भरोसा करने के बाद, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि धारा 14 किसी विदेशी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं थी। धारा 14 उन महिला हिंदुओं को लाभान्वित करना चाहती थी जो अधिनियम के प्रारंभ से पहले तत्कालीन मौजूदा हिंदू कानून में सीमित मालिक थीं।

* * * * * * *

निष्कर्ष में हमारा मानना है कि धारा 14 उन अन्य लोगों को लाभान्वित करने के लिए आगे नहीं आती है जिन्होंने अपनी आंखों से एक सीमित मालिक की संपत्ति खरीदी; धारा 14 को धारा में उल्लिखित किसी भी तरीके से संपत्ति प्राप्त करने वाली महिला हिंदू के सीमित हित को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था और जो अधिनियम के लागू होने के समय संपत्ति के वास्तविक या रचनात्मक कब्जे में थी। इसका कभी भी ऐसी हिंदू महिला के सीमित हित को बढ़ाने का इरादा नहीं था, जिसने अधिनियम के प्रारंभ से पहले या तो बिक्री विलेख या उपहार विलेख निष्पादित करके संपत्ति के कब्जे को अलग कर दिया हो। "

(41) ऊपर निर्दिष्ट मामलों के आधार से यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में अधिकार का भारी भार है कि अधिनियम की धारा 14 का उद्देश्य एक सीमित महिला हिंदू स्वामी के उत्तराधिकारियों को लाभ पहुंचाना नहीं था।

(42) तथापि, चिन्टी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के दृष्टिकोण पर विचार करना शेष है। यह अपीलार्थी की ओर से निर्भरता का मुख्य आधार है। निस्संदेह, यह प्राधिकरण अपीलार्थी के मामले को प्रत्यक्ष समर्थन प्रदान करता है। हालांकि, सबसे बड़े सम्मान के साथ, मैं उसमें व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से असहमत होना चाहूंगा। यह शायद ध्यान देने योग्य है कि मामला एक कठिन था जिसमें एक विधवा द्वारा अपनी बेटी के पक्ष में उपहार दिया गया था, जो उलटने वालों द्वारा चुनौती का विषय था और ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी के पक्ष में मामले की निष्पक्षता शायद अवचेतन रूप से बेंच के साथ तौली गई थी। यह एक पुरानी कहावत है कि कठिन मामले कभी-कभी खराब कानून बनाते हैं।

(43) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीश स्वयं उन विसंगत परिणामों के प्रति सचेत थे जो अनिवार्य रूप से उनके द्वारा स्वीकार की गई व्याख्या से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने पहले के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया कि यदि एक महिला दाता को धारा 14 का लाभ दिया जाता है तो यह एक विसंगति पैदा करेगा क्योंकि समान परिस्थितियों में एक पुरुष दाता एक सीमित मालिक बना रहेगा जबकि एक महिला दाता एक पूर्ण मालिक बन जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह देखकर इस पेटेंट कठिनाई को दूर कर दिया कि विसंगति धारा 14 में ही निहित थी। बड़े सम्मान के साथ मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है। धारा 14 की भाषा में भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जिसके कारण ऐसी विसंगति को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना आवश्यक हो। जैसा कि मैंने पहले देखा, धारा 14 की भाषा पर दो व्याख्याएँ स्पष्ट रूप से संभव थीं और निर्माण के स्वीकृत सिद्धांतों पर एक ऐसी व्याख्या से आसानी से बचा जा सकता था जिससे विसंगतियाँ होतीं। इस संदर्भ में यह फिर से ध्यान देने योग्य है कि पूर्ण पीठ ने केवल एक विसंगति देखी और शायद कई अन्य बातों से बेखबर थी जो आवश्यक रूप से भी उत्पन्न होंगी और जिसका विस्तृत संदर्भ मैंने निर्णय के पूर्व भाग में दिया है। फिर भी विद्वान न्यायाधीशों ने उस बिंदु या पृष्ठभूमि पर कानून के इतिहास का कम से कम संदर्भ नहीं दिया, जिसके आधार पर धारा 14 (1) का अधिनियमन आवश्यक था, जिसके आलोक में इसका अर्थ लगाया जाना था। धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण के लिए फिर से कोई संदर्भ नहीं दिया गया। मेरे विचार से स्पष्टीकरण की भाषा पूर्ववर्ती खंड की व्याख्या के लिए एक कुंजी प्रदान करती है और इस मामले को मैंने पहले विस्तार से बताया है।

(44) बड़े सम्मान के साथ मेरा यह भी विचार है कि निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्राधिकरण पर निर्भरता, जो पूर्ण पीठ के पास है, उचित नहीं प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि इसमें प्राथमिक निर्भरता गुम्मलपुरा तागीना मटाडा कोट्टुरूस्वामी बनाम सेत्रा वीरव्व और अन्य (ऊपर) पर की गई थी, जिसमें से एक व्यापक उद्धरण दिया गया था। हालाँकि, ये टिप्पणियां मेरे लिए मुद्दे के बिंदु से पूरी तरह से दूर हैं। उसमें चर्चा किए गए मामले का मूल यह था कि क्या धारा 14 केवल उन सीमित मालिकों की कल्पना करती है जो कब्जे में थे और उन लोगों की नहीं जो पहले से ही कब्जे से अलग हो चुके थे। धारा 14 में 'अभिभूत' शब्द का अर्थ निकालने के लिए पूरा जोर दिया गया था। विदेशियों के हितों के विस्तार का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठा और न ही सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुओं ने इसे दूर से छुआ था। प्रासंगिक टिप्पणियां वास्तव में रिपोर्ट के पैरा 10 में थीं, जिसका कोई संदर्भ नहीं दिया गया था और जैसा कि मैंने पहले ही देखा है कि वे टिप्पणियां एक विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं और संदर्भों में हरक सिंह बनाम कैलाश सिंह (उपर्युक्त) में पटना पूर्ण पीठ का अनुमोदन करती हैं। कुछ निर्भरता गोस्ता बिहारी बनाम हरिदास सामंत पर भी रखी गई थी, लेकिन बड़े सम्मान के साथ यह कहा जा सकता है कि निर्णय किसी भी तरह से व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की सहायता या समर्थन नहीं करता है। अमर सिंह और अन्य बनाम सेवा राम और अन्य (उपर्युक्त) वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ में स्पष्टतः विपरीत टिप्पणियों का सामना करते हुए एक पारित संदर्भ दिया गया था और इसके बजाय संक्षेप में यह कहा गया था कि पूर्ण न्यायपीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पंजाब मामले के साथ संघर्ष नहीं करता था। इस संबंध में ऐसा नहीं लगता है और इस निर्णय के पहले भाग में मेरे द्वारा उद्धृत टिप्पणियों का प्रासंगिक हिस्सा पूरी तरह से छूट गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के विद्वत वकील वेंकैया बनाम वीरय्या (उपर्युक्त) और हरक सिंह के मामले (उपर्युक्त) में पूर्ण पीठ के मामले में व्यक्त किए गए स्पष्ट विचारों को अपने प्रभुओं के ध्यान में नहीं लाने में विफल रहे। नतीजतन, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कोई संदर्भ नहीं दिया गया है और न ही उन्हें अलग किया गया है या समझाया गया है। अधिक कारणों से इस निर्णय पर बोझ डालने से बचने के लिए, मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि अनंत बंधु सेन मंडल बनाम चंचला बाला दासी (उपर्युक्त) में खंड पीठ ने चिंता के मामले (उपर्युक्त) में दृष्टिकोण पर गहराई से विचार किया और विस्तृत कारणों से उसी से भिन्न था। मैं इस संदर्भ में कलकत्ता पीठ के तर्क से पूरी तरह सहमत हूं।

(45) उपर्युक्त कारणों से, बहुत सम्मान और सम्मान के साथ मैं श्रीमती चिन्टी के मामले में पूर्ण पीठ के दृष्टिकोण के साथ अपनी असहमति दर्ज करूंगा।

(46) ऊपर दिए गए समान कारणों से, जिन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, यह माना जाना चाहिए कि इस न्यायालय की एकल पीठ का दृष्टिकोण श्रीमती चावली और अन्य बनाम हंसा और अन्य (13) में रिपोर्ट किया गया था, जहां तक उसकी मांग थी किसी हिंदू महिला लिमिटेड मालिक की पराई पत्नी को भी धारा 14 का लाभ देना गलत निर्णय है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य मुद्दे पर अपीलार्थी के पक्ष में मामला समाप्त होने के बाद प्रासंगिक टिप्पणियां पूरी तरह से एक सहायक आधार के रूप में की गई थीं। फैसले के संदर्भ से पता चलता है कि मामले के इस पहलू का फैसला इस तरह किया गया था जैसे कि यह पहली छाप थी। इस मुद्दे पर न तो गहराई से चर्चा की गई है और न ही मामले के कानून के द्रव्यमान का कोई संदर्भ है, लेकिन विद्वान न्यायाधीश के प्रति निष्पक्षता में यह कहा जा सकता है कि कम से कम इसका कुछ हिस्सा उनके निर्णय के बाद का है। इस मामले में टिप्पणियाँ मुख्य रूप से विदेशी लोगों के कब्जे के मुद्दे पर आधारित थीं। कोट्टूरू स्वामी के मामले (ऊपर) में न्यायाधीशों द्वारा 'कब्जे में' शब्द पर रखी गई व्याख्या पर भरोसा करते हुए अन्य लोगों के पक्ष में एक निष्कर्ष निकालने की मांग की गई थी। मैंने पहले ही ऊपर दिखाया है कि तर्क की यह प्रक्रिया न तो पर्याप्त थी और न ही उचित थी। सम्मान के साथ मैं उक्त निर्णय को रद्द कर दूंगा।

(47) इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि विधान के इतिहास और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए; धारा 14 (1) की भाषा और विशेष रूप से उसका स्पष्टीकरण; विसंगतियां जो क़ानून की किसी अन्य व्याख्या से उत्पन्न होंगी; और प्राधिकरण का भारी वजन, पूर्ण पीठ के समक्ष प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में वापस किया जाना चाहिए।

प्रेम, चांद जैन, न्यायमूर्ति - मैं सहमत हूँ।

एस. सी. मित्तल, न्यायमूर्ति - मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा